भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 722
(दिनांक 04.02.2026 को उत्तर देने के लिए)

विकास संचार एवं सूचना प्रसार योजना

722. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

श्रीमती पूनमबेन माडमः

श्री राहुल सिंह लोधीः

श्रीमती डी. के. अरुणाः

श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

श्री मनोज तिवारीः

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री गोडम नागेशः

श्री बलभद्र माझीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों (जैसे पीएम-जनमन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत) के लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी) योजना का विशेष रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना और ओडिशा के नबरंगपुर और मलकानगिरी जैसे आकांक्षी और

दूरस्थ जिलों जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्रों के संबंध में कोई परिणाम-आधारित मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पहुँच, रिकॉल और व्यवहारिक प्रभाव से संबंधित संकेतकों सहित ऐसे मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के माध्यम से किए गए आउटरीच का वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के नबरंगपुर और मलकानगिरी जिलों और महाराष्ट्र के जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकांक्षी जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले, तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमराम भीम-आसिफाबाद और निर्मल जिलों और ओडिशा के नबरंगपुर, मलकानगिरी जिलों, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आउटरीच बढ़ाने के लिए कोई क्षेत्र-विशिष्ट (जैसे 'बघेली' बोली) या भाषा-आधारित (जैसे तेलुगु भाषा और जनजातीय बोली) संचार रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं;

(घ) यदि हों, तो इन स्थानीय समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए तैनात आउटरीच ब्यूरो और फील्ड चार्ज इकाइयों द्वारा अपनाए गए मीडिया मिक्स, स्थानीय भाषा की सामग्री और की गई गतिविधियों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) तेलंगाना में युवाओं और ग्रामीण आबादी के बीच बदलते मीडिया उपभोग पैटर्न को देखते हुए डिजिटल और सोशल मीडिया आउटरीच को मजबूत करने, उभरते प्लेटफॉर्म और एनालिटिक्स के उपयोग के लिए योजना के अंतर्गत प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन उपायों से ओडिशा के नबरंगपुर और मलकानगिरी जिलों में विशेष रूप से सूचना प्रसार में किस प्रकार सुधार होने की संभावना है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (च): विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। यह प्रामाणिक, तथ्यात्मक और लाभार्थी-केंद्रित सूचना का अंतिम छोर तक प्रसार और सरकारी कार्यक्रमों/स्कीमों/पहलों की नागरिक पहुंच सुनिश्चित करती है।

यह स्कीम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसकी मीडिया यूनिटों केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) और न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) के माध्यम से लागू की जाती है।

डीसीआईडी स्कीम के तहत, सीबीसी और पीआईबी विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में सूचना के प्रसार के लिए वार्ताओं (मीडिया कार्यशालाओं), वार्तालाप (मीडिया कॉन्क्लेव) और प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित कई सार्वजनिक मल्टीमीडिया अभियानों, आउटरीच कार्यकलापों का संचालन करते हैं। सरकार स्कीमों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए इनका नियमित रूप से मूल्यांकन करती है।

शहडोल, आदिलाबाद, कुमराम भीम-आसिफाबाद, निर्मल, नबरंगपुर, मलकानगिरी और जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे भारत में प्रामाणिक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं और बोलियों में सूचना का प्रसार किया जाता है।

डिजिटल मीडिया स्पेस में युवाओं और लक्षित दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए विविध डिजिटल आउटरीच प्लेटफार्मों पर लक्षित संचार अभियान चलाए जाते हैं। यह भारत सरकार की डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के अनुसार किया जाता है।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) नबरंगपुर और मलकानगिरी जैसे जिलों में संचालित अभियान सहित सभी मीडिया अभियानों की योजना विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकताओं और संबंधित कार्यक्रमों के विशिष्ट लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखते हुए तैयार करता है।

*****